

पैन पॉवर

हिंदी दैनिक समाचार पत्र

वर्ष - 1 अंक - 34

शुक्रवार, अगस्त 14, 2026

विशाखापट्टनम

संपादक: गंट्यादा अप्पाराव

पृष्ठों. 4मूल्य. 1₹

डीएससी पर झूठा प्रचार करने वालों को बरख़्तो नहीं, जोरदार जवाब दें: मंत्रियों से चंद्रबाबू



(पैन पॉवर न्यूज़): अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एपीपीएससी ग्रुप-1 परीक्षा के मूल्यांकन के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) पूरी तरह बेनकाब हो गई है। उन्होंने चिंता जताई कि अपने लोगों को नौकरियां दिलाने के लिए योग्य उम्मीदवारों को कथित तौर पर बलि का बकरा बनाया गया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने गुरुवार दोपहर सचिवालय में उपलब्ध मंत्रियों के साथ लंच मीटिंग की। इस दौरान ग्रुप-1 का मुद्दा चर्चा में आया। ग्रुप-1 मूल्यांकन में 97 प्रतिशत उत्तर पुस्तिकाओं की जांच किए जाने पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू और मंत्रियों ने आश्चर्य व्यक्त किया। मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कई अखबारों और टीवी चैनलों में प्रकाशित खबरों में डेटा एंट्री ऑपरेटरों से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराए जाने की बात सामने आने से सभी हैरान हैं। मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से आगामी विधानसभा सत्रों में ग्रुप-1 मामले को लेकर

वाईएसआरसीपी को घेरने का भी आग्रह किया। मंत्रियों ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पिछली वाईएसआरसीपी सरकार और तत्कालीन एपीपीएससी सचिव पी.एस.आर. आंजनेयुलु की भूमिका की गहन जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य अधिकारियों की भूमिका भी हो सकती है और इसकी भी जांच की जानी चाहिए। मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में आगे जांच कराने का अनुरोध किया। मंत्रियों ने याद दिलाया कि 2011 में महाराष्ट्र में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जिसके बाद उम्मीदवारों ने आंदोलन किया था। इस पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट फिलहाल अदालत के विचाराधीन है और न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एपीपीएससी ग्रुप-1 परीक्षा मामले में किन-किन लोगों की भूमिका रही, इसकी जानकारी जुटाने के लिए पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री अनगानी सत्य प्रसाद ने बताया कि जिन ग्रुप-1 उम्मीदवारों ने अपने साथ

अन्याय होने का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया है, उनसे बात करने पर पूरी जानकारी मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उनसे तुरंत बात कर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। वहीं, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट किया कि डीएससी भर्ती में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि वाईएसआरसीपी इस मुद्दे को विधान परिषद में उठाती है तो सरकार इसका जोरदार जवाब देगी। उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वाईएसआरसीपी के हर आरोप का सबूत और दस्तावेजों के साथ आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जवाब भी मजबूत होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधान परिषद में डीएससी मामले पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है और आरोप लगाने वालों को सबूत पेश करने की चुनौती दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी पहले ही सभी मामलों पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। इसके बावजूद अगर जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो

राजनीतिक रूप से उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। चंद्रबाबू ने यह भी कहा कि राजधानी अमरावती में निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अब लगातार उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने मंत्रियों के साथ साइबराबाद के विकास, हैदराबाद आउटर रिंग रोड और हाईटेक सिटी जैसी परियोजनाओं में अपने अनुभव भी साझा किए।

श्रद्धालुओं के लिए अलर्ट: इंद्रकीलाद्रि पर नए सुरक्षा नियम

विजयवाड़ा, 13 अगस्त: इंद्रकीलाद्रि स्थित प्रसिद्ध कनक दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर अधिकारियों ने नए सुरक्षा नियम लागू किए हैं। मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कैनिंग प्वाइंट पर नया सुरक्षा गेट लगाया गया है और स्कैनिंग के बाद मोबाइल फोन अंदर न ले जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी जांच की जाएगी। नए नियमों के तहत श्रद्धालुओं को क्यू लाइन में प्रवेश करने से पहले मोबाइल फोन जमा करना होगा। मोबाइल फोन जमा करने के लिए विशेष डिपॉजिट काउंटर बनाए गए हैं। मंदिर की ईओ शीना नायक ने सुरक्षा जांच को और कड़ा करने के निर्देश दिए हैं। मंदिर अधिकारियों ने बताया कि होमगार्ड और एजाइल सिक्योरिटी कर्मचारियों की मदद से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। भीड़ नियंत्रण के लिए दर्शन की कतारों में भी बदलाव किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार दर्शन टिकट जारी करने वाले काउंटरों के स्थान बदले गए हैं। मुफ्त लड्डू प्रसाद वितरण काउंटरों को भी स्थानांतरित किया गया है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और वे सीधे दर्शन के लिए जा सकें, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से नए सुरक्षा नियमों में सहयोग करने की अपील की है।



एनटीआर के दौर की राजनीति फिर लौटनी चाहिए: अय्यन्ना पात्रुडु

(पैन पॉवर न्यूज़): गुंटूर जिला, 13 अगस्त: आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष चिंताकायला अय्यन्ना पात्रुडु ने इच्छा जताई कि दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव के दौर की राजनीति फिर से लौटनी चाहिए। उन्होंने राजनीति में आने की इच्छा रखने वालों को वरिष्ठ नेता कन्ना लक्ष्मीनारायण से बहुत कुछ सीखने की सलाह दी। गुरुवार को गुंटूर जिले में मीडिया से बात करते हुए अय्यन्ना पात्रुडु ने कहा कि आजकल लोग एक बार

किसी को वोट देने के बाद दूसरी बार उसी उम्मीदवार को वोट नहीं देते। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत कन्ना लक्ष्मीनारायण ने लोगों का विश्वास और समर्थन हासिल कर छह बार चुनाव जीता। अय्यन्ना ने कहा कि पहले के समय के लोग और नेता आज जैसे नहीं रहे। उन्होंने कन्ना के अनुशासन, लोगों से मिलने पर उनका अभिवादन करने और किसी का काम संभव होने पर उसे पूरा कराने की उनकी विशेषता की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि कन्ना ने लोगों की जरूरतों को समझकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम किया। अय्यन्ना पात्रुडु ने कहा कि अगर अन्य नेता भी कन्ना की तरह काम करें तो आंध्र प्रदेश बेहतर स्थिति में पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि आज राजनीति व्यवसाय बन गई है। अय्यन्ना पात्रुडु ने कन्ना लक्ष्मीनारायण के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि वे आगे भी लंबे समय तक जनता की सेवा करते रहें।



टीडीपी और वाईएसअरसीपी के आमने-सामने कार्यक्रम, ताड़ीपत्री में तनाव

(पैन पॉवर न्यूज़): अनंतपुर, 10 अगस्त: ताड़ीपत्री में टीडीपी और वाईएसअरसीपी नेताओं द्वारा एक-दूसरे के समानांतर कार्यक्रम आयोजित किए जाने से तनाव का माहौल बन गया। पूर्व विधायक केतिरड्डी पेद्दारेड्डी ने मेगा डीएससी भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए रैली का आह्वान किया। वाईएसअरसीपी कार्यालय से वाईएसआर सर्किल तक विरोध रैली निकालने का निर्णय लिया गया। इसके चलते बड़ी संख्या में वाईएसअरसीपी कार्यकर्ता पेद्दारेड्डी के आवास पर पहुंच गए। रैली शुरू होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पेद्दारेड्डी को उनके घर पर ही रोक दिया। इसके बाद पुलिस और वाईएसअरसीपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। वाईएसअरसीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। दूसरी ओर, पूर्व विधायक जेसी प्रभाकर रेड्डी ने

ताड़ीपत्री में 'इंटिटिकी तेलुगु देशम' कार्यक्रम आयोजित किया। इसके चलते बड़ी संख्या में टीडीपी कार्यकर्ता उनके आवास पर जुटने लगे। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया कि ताड़ीपत्री में वाईएसअरसीपी और टीडीपी के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने कहा कि शहर के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। वाईएसअरसीपी के रायलसीमा समन्वयक पेद्दिर्रेड्डी रामचंद्र रेड्डी और पार्टी के जिला अध्यक्ष अनंता वेंकटरामिरेड्डी भी ताड़ीपत्री के लिए रवाना हुए। हालांकि, पुलिस ने मुच्चुकोटा इलाके में पेद्दिर्रेड्डी रामचंद्र रेड्डी को रोक दिया। पेद्दिर्रेड्डी के ताड़ीपत्री जाने पर अड़े रहने के बावजूद पुलिस ने साफ कर दिया कि बाहरी लोगों को ताड़ीपत्री में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद पेद्दिर्रेड्डी रामचंद्र रेड्डी और अनंता वेंकटरामिरेड्डी की पुलिस के साथ तीखी बहस हुई।

मेरिट, पारदर्शिता और न्याय ही भर्ती के मानक: डोला वीरांजनय स्वामी

(पैन पॉवर न्यूज़): अमरावती, 13 अगस्त: आंध्र प्रदेश के मंत्री डोला बाला वीरांजनय स्वामी ने कहा कि राज्य में गठबंधन सरकार ने 16 हजार से अधिक डीएससी पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती की है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू सरकार का सिद्धांत है कि किसी भी मेधावी उम्मीदवार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर की जा रही भर्तियां 20 लाख नौकरियों के वादे के तहत की जा रही हैं। मंत्री ने कहा कि डीएससी भर्ती के खिलाफ दायर सैकड़ों मामलों

को सरकार ने कानूनी रूप से पार करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए विपक्ष अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है। पिछली सरकार के कार्यकाल में एपीपीएससी ग्रुप-1 परीक्षा के संबंध में मंत्री ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सवाल किया कि अयोग्य लोगों से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने के आरोपों का जवाब क्या है। उन्होंने पूछा कि निजी रिसॉर्ट में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्यों किया गया, सीसीटीवी कैमरों और आधि

कारिक निगरानी के बिना मूल्यांकन कैसे हुआ तथा एपीपीएससी के कब्जे में रहने वाली उत्तर पुस्तिकाएं निजी स्थान तक कैसे पहुंचीं। उन्होंने व्यक्तिगत जीमेल खातों और गूगल ड्राइव के माध्यम से मूल्यांकन किए जाने के आरोपों पर भी स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने मूल्यांकन पैनल की योग्यता पर उठे सवालों का जवाब देने की मांग की। मंत्री ने कहा कि एसआईटी द्वारा चिन्हित अंकों में अंतर के संबंध में पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि ओएमआर शीट में किए गए सुधारों और व्हाइटनर के इस्तेमाल पर फोरेंसिक रिपोर्ट

में क्या कहा गया है। उन्होंने अलग-अलग स्याही के इस्तेमाल और ऐसे सुधारों की जांच की मांग की जिन पर हस्ताक्षर मेल नहीं खाते। उन्होंने सवाल किया कि एक ही उत्तर पुस्तिका में अलग-अलग स्याही का इस्तेमाल क्यों किया गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं साबित होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मंत्री ने कहा कि किसी को भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय डीएससी



भर्ती से जुड़े तथ्य और सबूत पेश करने की चुनौती दी। "मेरिट, पारदर्शिता और न्यायकू गठबंधन सरकार की भर्ती प्रक्रिया में यही मानक हैं," मंत्री डोला बाला वीरांजनय स्वामी ने स्पष्ट किया।

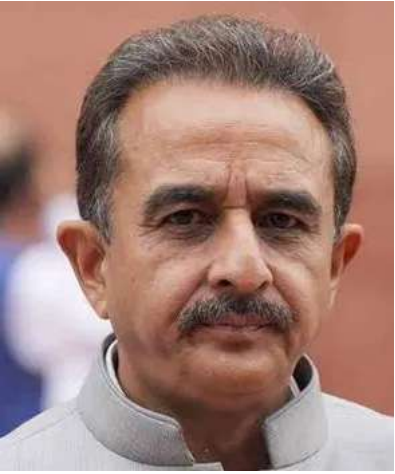
हाथियों और लोगों की जान की रक्षा सरकारों की जिम्मेदारी: कीर्ति वर्धन सिंह

(पैन पॉवर न्यूज़): विशाखापत्तनम, 13 अगस्त: केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि हाथियों के संरक्षण के साथ-साथ लोगों की जान और आजीविका की रक्षा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विशाखापत्तनम में आयोजित विश्व हाथी दिवस-2026 के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मानव-हाथी संघर्ष एक गंभीर समस्या बन गया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के लिए अस्थायी उपायों के बजाय वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित व्यापक योजना की आवश्यकता है। हाथियों के संरक्षण में प्रगति के बावजूद फसल नुकसान, लोगों की मौत और हाथियों की मृत्यु की घटनाएं बढ़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस पृष्ठभूमि में हाथी संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है।

विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हुए बंदी हाथियों का डीएनए डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। साथ ही हाथियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए 'गज सूचना' ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथियों के व्यवहार का अध्ययन करने में यह ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। **रेलवे ट्रैक के पास उठाए जा रहे कदम** केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेलवे विभाग के साथ समन्वय कर संवेदनशील क्षेत्रों में अंडरपास, फेंसिंग और चेतावनी प्रणाली स्थापित की जा रही है। बिजली की लाइनों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भी आवश्यक कदम

उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सिकिम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में तीन नए हाथी रिजर्व बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि



मानव-हाथी संघर्ष का कोई एक समाधान नहीं हो सकता। प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष के कारणों की पहचान कर उसी के अनुसार उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने अस्थायी उपायों तक सीमित रहने के

बजाय पूर्वानुमान आधारित व्यवस्था विकसित करने की जरूरत बताई। कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। राज्यों के बीच अनुभव साझा करने से अधिक प्रभावी समाधान तलाशे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि हाथियों के संरक्षण और मानव-हाथी संघर्ष की रोकथाम के लिए ६500 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। इस राशि से वैज्ञानिक उपायों को बड़े स्तर पर लागू किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाथियों, लोगों की जान और उनकी आजीविका की रक्षा करना सरकारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय से ही मानव-हाथी संघर्ष का दीर्घकालिक समाधान संभव है।

वाईएसअरसीपी के उकसावे के बावजूद किसानों ने अमरावती का समर्थन किया: मंत्री नारायण

(पैन पॉवर न्यूज़): अमरावती, 13 अगस्त: मंत्री नारायण ने कहा कि आंध्र प्रदेश एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जहां उसकी कोई राजधानी नहीं थी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के लिए एक आर्थिक राजधानी बनाने का विचार किया। गुरुवार को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने सीड एक्सेस रोड के दूसरे चरण और बकिंघम नहर पर बने स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि तेलंगाना की आय का बड़ा हिस्सा हैदराबाद से आता है। इसी तरह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु को क्रमशः मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से आर्थिक लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि आर्थिक राजधानी के निर्माण के लिए सिंगापुर सरकार ने मुफ्त में मास्टर प्लान उपलब्ध कराया था। प्रतिष्ठित इमारतों के निर्माण के लिए लंदन की नॉर्मन फोस्टर कंपनी से भी संपर्क किया गया था।

उन्होंने कहा कि कृष्णा नदी के किनारे अमरावती का निर्माण करने से राज्य के सभी जिलों के साथ समान न्याय होगा। मंत्री ने कहा कि अमरावती श्रीकाकुलम से अनंतपुर के बीच लगभग केंद्रीय स्थान पर है और यहां रेल तथा सड़क दोनों तरह की कनेक्टिविटी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2015 में लैंड पूलिंग की अधिसूचना जारी की गई थी और किसानों ने केवल 58 दिनों में बिना किसी मुकदमे के 34,000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई थी। उन्होंने कहा कि अमरावती में काम शुरू करने, टेंडर बुलाने और अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने में साढ़े तीन साल लगे। इसके बाद बचे डेढ़ साल में अमरावती के लिए 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस बीच वाईएसआरसीपी सत्ता में आई और उसने तीन राजधानियों की योजना के नाम पर अमरावती का निर्माण रोक दिया, मंत्री ने आरोप लगाया। उन्होंने



कहा कि निर्माण कंपनियों के साथ हुए समझौतों को भी उचित तरीके से बंद नहीं किया गया। गठबंधन सरकार के सत्ता में लौटने के बाद संबंधित कंपनियों के साथ पुराने समझौतों को तकनीकी रूप से बंद कर फिर से टेंडर बुलाने पड़े। नारायण ने बताया कि पहले किए गए कार्यों की गुणवत्ता की जांच आईआईटी चेन्नई और आईआईटी हैदराबाद के विशेषज्ञों से कराने के बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया गया। उन्होंने

कहा कि सीड एक्सेस रोड के साथ बिजली, गैस, टेलीफोन और पानी जैसी सुविधाओं के लिए भूमिगत व्यवस्था की योजना बनाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी ने किसानों को अमरावती के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद किसानों ने अमरावती के निर्माण में सहयोग किया। नारायण ने अमरावती के निर्माण में भाग लेने का अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू को धन्यवाद दिया।

संपादकीय

एक न्यायाधिकरण, जो अपने आप में पूर्ण है

हमारे सार्वजनिक अधिनियमों में न्यायाधिकरणों के गठन से जुड़े कुछ ही प्रश्न ऐसे हैं, जिनकी इतनी बार पुनर्समीक्षा हुई है। 1987 के एस. पी. संपत कुमार मामले से लेकर नवंबर 2025 में मद्रास बार एसोसिएशन से संबंधित निर्णय तक, न्यायालयों ने कानून निरस्त किये, निर्देश जारी किए और फिर उसी आधार पर स्वयं को नए कानूनों की समीक्षा करते हुए पाया। यह विषय इतने चक्र से गुजर रहा है, जो अपने आप में दर्शाता है कि समस्या कितनी कठिन रही है। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 इसीलिए ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अंततः वास्तविक समस्या की पहचान कर ली है और उम्मीद है कि समाधान भी खोज लिया है। यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। दूसरे देशों को भी इसका सामना करना पड़ा है और उनका निदान ध्यान देने योग्य है। ब्रिटेन में जब सर एंड्रयू लेगट ने 2001 में इस क्षेत्र की समीक्षा की, तो पाया कि सत्तर से अधिक न्यायाधिकरणों का प्रशासन उन्हीं विभागों द्वारा किया जा रहा था, जिनके निर्णयों की वे समीक्षा करते थे। उन्होंने इसे मूल दोष माना। उनका उपाय कार्यकाल में बदलाव या योग्यताओं को परिष्कृत करना नहीं था। उनका समाधान था कि न्यायाधिकरणों को उनके प्रायोजक विभागों से अलग कर उनका प्रशासन एकल सेवा के अधीन किया जाए। यही सुधार 2007 के अधिनियम का आधार बना। यह सुधार संरचनात्मक था। उसने निर्भरता के लक्षणों को नहीं, बल्कि निर्भरता की वजह का समाधान किया। भारत ने न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को प्रारंभिक चरण में ही अपनाया और, कुल मिलाकर, यह सफल रही। 1941 में स्थापित आयरक अपीलौय न्यायाधिकरण आज भी विशेषज्ञतापूर्ण न्यायनिर्णयन के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। इस प्रारूप को अनुच्छेद 323ए और 323बी तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 द्वारा आगे बढ़ाया गया और बाद में विभिन्न न्यायक क्षेत्रों में उस उच्च स्तर पर इसका विस्तार हुआ, जिसे उच्च न्यायालय नहीं ले सकते थे। पर हमारी समस्या अलग तरह की थी। जैसा कि न्यायालय की 2020 की रिप्पणी में कहा गया कि स्वतंत्रता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब न्यायाधिकरणों को अपने कार्य करने के लिए कार्यपालिका के कंधों का सहारा न लेना पड़े। इस बारे में सुधार एक से अधिक बार किए गए हैं और हर बार सच्ची भावना के साथ किए गए हैं। इसके बाद होने वाली अधिकांश मुकदमेबाजी इस बात को लेकर रही कि कार्यकाल तीन वर्ष का होना चाहिए या चार या पांच वर्ष का, न्यूनतम आयु पचास वर्ष होना स्वीकार्य है या नहीं, और एक नाम या दो नामों की समिति की सिफारिश होनी चाहिए। सम्मानपूर्वक कहना होगा कि इनमें से कोई भी बात मूल समस्या तक नहीं पहुंचती। स्वतंत्र न्यायाधिकरण अंकगणित पर निर्भर नहीं करते। कार्यकाल, आयु और नामों की संख्या ये लक्षण हैं जिनके माध्यम से रोज का निदान किया गया है। वे स्वयं बीमारी नहीं हैं। मूल बात यह है कि न्यायाधिकरण एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर संस्था होनी चाहिए। उसका अपना साधन होना चाहिए, उन पर निगरानी रखने और उन्हें अनुशासित करने की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए तथा परिसर, कर्मचारियों और धन की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। जहां ये सभी व्यवस्थाएं मौजूद हों, वहां स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। नया विधेयक उन सभी बिंदुओं पर न्यायालय को उत्तर देता है, जिन पर न्यायालय अपनी बात कह चुका है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक ऐसी संस्था स्थापित करने का प्रयास है जो उन उत्तरों को स्वयं लागू करने योग्य बना दे। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना कानून द्वारा की जानी है। उसका अस्तित्व, गठन और कार्य किसी कार्यपालिका आदेश से नहीं, बल्कि अधिनियम से संचालित होंगे और उसे चयन, निगरानी, अनुशासन तथा न्यायाधिकरणों की आवश्यकताओं के आकलन का दायित्व है। उसके चारों ओर एक स्थायी पेशेवर सचिवालय स्थापित किया जाएगा। विधेयक में उन प्रत्येक बिंदुओं पर न्यायिक सर्वोच्चता बनाए रखी गयी है, जहां उसका महत्व है। आयोजन की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और उसमें न्यायिक बहुमत का प्रावधान है। समितियों की अध्यक्षता न्यायिक रूप से की जाती है तथा निर्णायक मत न्यायिक अध्यक्ष का सा हो होता है। चयन, निगरानी, अनुशासन और कार्य-प्रदर्शन—सभी का नेतृत्व न्यायिक तौर पर किया जाता है। यह उस बात के अनुरूप है जो न्यायालय आर. गांधी मामले के बाद से कहता आया है कि कार्यपालिका, जो सबसे बड़ी वादी है, उन लोगों के चयन में प्रमुख भूमिका नहीं निभा सकती जो उसके मामलों का निर्णय करते हैं। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण यह है कि सर्वोच्चता का अर्थ नियंत्रण नहीं है। पूरी व्यवस्था न्यायिक पक्ष को सौंप देना भी चुनौतियों के रूप में देखा जाता है। इसलिए यह विधेयक न्यायाधिकरण को तीन स्तरों से कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान दूरी पर रखता है। केद्र सरकार नियमों द्वारा व्यापक सिद्धांत निर्धारित करती है। आयोग उन नियमों को लागू करने के तरीके को नियंत्रित करने वाले विनियम बनाता है। सचिवालय इसी ढांचे के तहत काम करता है। उसे कार्य करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है, लेकिन परिचालन स्तर पर उसे निर्देशित नहीं किया जाता और वह अपने कार्य अधिनियम से प्राप्त करता है, न कि अधिकार या कार्य किसी दूसरे को सौंपे जाने के प्रत्यायोजन से। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग, सचिवालय और कार्यपालिका के संयोजन से उत्पन्न नियंत्रण और संतुलन की वास्तविक व्यवस्था है। सचिवालय पात्रता की जांच और उसका अभिलेखित तैयार करेगा, जिसके आधार पर प्रत्येक निर्णय लिया जाना है। वह प्रकाशित विनियमों से बंधा है और अपने कार्यों का रिकॉर्ड रखेगा। विधेयक द्वारा कायम यही वह नाजुक संतुलन है। इसमें न तो प्रशासन में न्यायिक हस्तक्षेप है और न ही वास्तविक रूप से कार्यपालिका पर निर्भरता, जबकि चयन, निगरानी, अनुशासन और कार्य-प्रदर्शन में न्यायिक सर्वोच्चता बनी रहती है। कनाडा ने 2014 में इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया था, जब उसने अपने संघीय न्यायाधिकरणों की सहायक सेवाओं के एक ही संगठन के अधीन लाते हुए उनके न्यायनिर्णयन संबंधी स्वतंत्रता बरकरार रखी। इस प्रकार के कानून का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि वह न्यायिक चुनौती में टिकता है या नहीं। इसका मूल्यांकन इस तथ्य के आधार पर होना चाहिए कि क्या वह उन स्थितियों को समाप्त करता है, जिनसे ये चुनौतियां पैदा हुईं। विधेयक इस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। यदि यह अपने निर्धारित स्वरूप में काम करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि न्यायाधिकरण व्यवस्था के काफी सुधार आएगा। इसमें वादी को अंततः ऐसा मंच मिलेगा जो उचित रूप से गठित, पर्याप्त रूप से व्यवस्थित होगा, जहां रिकित्यां समय पर भरी जाएंगी तथा जो अपने कार्य-प्रदर्शन के लिए जवाबदेह होगा। विकसित किया गया यह मॉडल, यदि सफल रहा तो भविष्य में अन्य प्रकार के चयन के लिए भी काफी उपयोगी होगा।

असामाजिक हो रहे सोशल मीडिया का नियमन जरूरी

सोशल मीडिया को लोकतंत्र के बड़े मंच के रूप में 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनिशिया के सिटी बौजिज शहर में फलों का ठेला लगाने वाले मोहम्मद बोआजीजी की आत्महत्या के बाद हुए उबाल के बाद देखा जाने लगा। म्यूनिसिपल कर्मचारियों की सख्ती के चलते क्षुब्ध बोआजीजी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। दिल्ली में बीस जुलाई को काकोरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के जेन जी के संबोधन की वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत चर्चा में हैं। चर्चा से ज्यादा उनकी भूमिका कहीं ज्यादा विमर्श के केंद्र में है। इसमें दो राय नहीं कि दुनियाभर में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रचलन में हैं, उनमें से ज्यादातर विदेशी हैं। जाहिर है कि वे उन जगहों के कानूनों और सांस्कृतिक परंपराओं से ज्यादा संचालित हैं, जहां उनके मुख्यालय हैं। इसलिए अपने व्यापक हितों के लिए वे अपने प्रचलन वाले देशों की परंपराओं और संस्कृतियों को सवालों के घेरे में लाने, उसका उन्हास उड़ाने और उन्हें तार-तार करने वाला अलगोरिदम उन्होंने विकसित कर रखा है। जिसका खामियाजा तीसरी दुनिया के देश रूप में 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनिशिया के सिटी बौजिज शहर में फलों का ठेला लगाने वाले मोहम्मद बोआजीजी की आत्महत्या के बाद हुए उबाल के बाद देखा जाने लगा। म्यूनिसिपल कर्मचारियों की सख्ती के चलते क्षुब्ध बोआजीजी ने खुद पर पेट्रोल डालकर

आग लगा ली। किसी ने इस घटना को सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया के तत्कालीन अलगोरिदम ने इस घटना को इस रूप में प्रस्तुत किया कि समूचे अरब जगत में उबाल आ गया। नागरिक अधिकारों की स्थापना और लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर अरब देशों की जनता सड़कों पर उतर आई। इसका ही नतीजा मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर चौक पर दिखा। जहां महीनों तक लोग जमे रहे और वहां के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। यह आग सीरिया, यमन और लीबिया तक जा पहुंची। वहां के पारंपरिक शासकों के खिलाफ लोगों का दबा हुआ गुस्सा निकला और कई जगह सत्ताएं बदल गईं। भारत में भी इसके ही कुछ महीनों बाद अन्ना हजारे को आगे रखकर एक आंदोलन छेड़ा गया। जिसकी परिणति आम आदमी पार्टी के रूप में हुई और वह दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई। फिर पंजाब में भी उसने पैठ बना ली। इन घटनाओं को याद करना इसलिए जरूरी है कि इन सबके पीछे सोशल मीडिया के जरिए त्वरित गति से फैलाई गई सूचनाओं का हाथ सबसे ज्यादा रहा। तब सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया गया। सोशल मीडिया के बारे में कहा गया कि लोकतंत्र में सबकी आवाज पहुंचाने और उन्हें मौका देने का यह बड़ा माध्यम है। इसे लोकतंत्र के वाजिब और जरूरी औजार के रूप में भी मान्यता मिली। लेकिन बीतेते वक्त के साथ पता चल रहा है कि जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, वह लोकतंत्र के लिए जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा अनसोशल यानी असामाजिक भी है। यह ठीक है कि सोशल मीडिया के जरिए व्यवस्था की अंधी सुरंग में खो रही आवाजों को मौका मिलता है। लेकिन



यह उतना ही सच है कि इस माध्यम ने लोगों की नजर का पानी उतार दिया है। लोग अब लिहाज करना भूल गए हैं। सोशल मीडिया पर अगर किसी की बात पसंद नहीं आती तो उसे खुलेआम गालियां दी जा सकती हैं। उसके चरित्र पर आक्षेप लगाया जा सकता है। उसका चरित्र हनन किया जा सकता है। चाहे वह व्यक्ति सामाजिक जीवन में कितना ही प्रतिष्ठित क्यों न हो, उसकी उम्र चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सोशल मीडिया मंचों ने अपना अलगोरिदम भी ऐसा विकसित किया है, जो अच्छी बातों, सामाजिक चिंतन और बेहतर कल की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देखा। एक तरह से कहें तो वह इसकी अनदेखी ही करता है। लेकिन जैसे ही किसी को कोई गाली देता है, किसी के चरित्र का बेवजह ही हनन करता है, किसी का घटिया कार्टून बनाता है, सोशल मीडिया का अलगोरिदम उसे फैलाने में द्रुत गति से जुट जाता है। सोशल मीडिया ने अब तक पर्दे के पीछे रही नंगई को भी उजागर कर दिया है। आज रीलस के चक्कर में अधमगे और कई बार करीब-करीब नम्र फोटोग्राफ

और वीडियो तक जारी किए जा रहे हैं। भले ही अपने परिवारों में महिलाएँ और युवतियां सलीके से रहती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने और उसके जरिए कुछ कमाने के चक्कर में अपने शील और अपनी लज्जा को भी बेपर्दा कर रही हैं। सोशल मीडिया कितना असमाजिक हो चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसका अलगोरिदम अस्लीलता को बढ़ावा देता है, लेकिन शील और लज्जा की बात को अपने मंच के किसी कोने में डाल देता है। कह सकते हैं कि वर्चुअल स्पेस के किसी अंधेरे कोने में उसे गुम कर देता है।तीन साल पहले यू रिसर्च सेंटर ने 19 विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में सोशल मीडिया को लेकर एक शोध किया था। उसके मुताबिक, आम नागरिकों की नजर में सोशल मीडिया राजनीतिक जीवन के लिए रचनात्मक और विनाशकारी दोनों है। इस अध्ययन में शामिल देशों में, औसतन 5.7 प्रतिशत लोगों ने माना कि सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लेकिन इसे बिनाशकारी मानने वालों की संख्या भी कम

नहीं रही। करीब 35 प्रतिशत से ज्यादा लोगों का का कहना था कि सोशल मीडिया विनाशकारी साबित हो रहा है। सिर्फ 34 प्रतिशत अमेरिकियों ने ही सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए लाभकारी माना, जबकि 64 फ्रीसद का कहना था कि इसने नकारात्मक प्रभाव ज्यादा डाला है। हाल ही में जेन जी से चर्चा के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी सोशल मीडिया को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उसमें उन्होंने कहा है कि यदि सोशल मीडिया पर उनके कारण दस लाख लोग कोई गलत निर्णय लेते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। सोशल मीडिया पर सकारात्मक, उपयोगी और समाजहित की सामग्री साझा करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर केवल प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। जेन-जी में भी यह विवेक विकसित होना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं। वरिष्ठ पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है कि वह नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करे तथा उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझाए। सोशल मीडिया का अनसोशल चेहरा और मंच आर्थिक कमाई का जरिया भी है। नंगई, हिंसा और व्यभिचार-अतिचार की कहानियां, दूषण, वीडियो और फोटो को वायरल करने में उसका कोई सानी नहीं है। इस बहाने इसे प्रसारित करने वाले को सोशल मीडिया मंच आर्थिक कमाई भी कराते हैं। और तो और, वे खुद भी ऐसी घटनाओं, दूषणों को प्रसारित-प्रचारित और वायरल करने के लिए बड़ी रकम लेते हैं। संसदीय समिति के सामने फेसबुक और इंस्टाग्राम की संचालक कंपनी के अधिकारियों ने माना है कि काकोरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान गाली, हिंसा आदि को बढ़ावा देने के लिए पैसे भी लिए थे।

इधर एक रक्षा समझौता कर उछल रहा पाकिस्तान

भारत के लिए दूसरा बड़ा मोर्चा अरब जगत में उसकी बढ़ती रक्षा साझेदारी है। यूएई द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि इसी रणनीतिक समीकरण को बदल सकती है। यदि सौदा अंतिम रूप लेता है तो यह खाड़ी में भारत की शक्तिशाली संकेत होगी। भले ही तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान 7 अगस्त 2026 के मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के बाद इसे अपनी बड़ी रणनीतिक कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हों, लेकिन भारत ने इस बदलते शक्ति-संतुलन का जवाब किसी एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि कई दिशाओं में पहले ही तैयार कर लिया था। सिर्फ एक साल के ही घटनाक्रमों को देखें तो फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को Special Strategic Partnership for Peace, Innovation and Prosperity के स्तर तक पहुंचाया और रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, साइबर तथा अत्याधुनिक तकनीकों में सहयोग को नई धार दी। उसी फरवरी में फ्रांस के साथ रिश्तों को 'Special Global Strategic Partnership' तक पहुंचाया गया, जिसके तहत रक्षा उत्पादन, HAMMER मिसाइलों के भारत में संयुक्त निर्माण और उन्नत सैन्य तकनीक पर सहयोग बढ़ा है। इससे पहले अगस्त 2025 में फिलीपींस के साथ भारत ने Strategic Partnership स्थापित की थी, जिसके केंद्र में रक्षा, समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत



सहयोग है। साथ ही अप्रैल 2026 में दक्षिण कोरिया के साथ Special Strategic Partnership को अगले पांच वर्षों के लिए नई रणनीतिक दिशा दी गई, जबकि मई 2026 में वियतनाम के साथ Enhanced Comprehensive Strategic Partnership के तहत रक्षा खरीद, समुद्री सुरक्षा, साइबर सहयोग और हिंद-प्रशांत में समन्वय को और मजबूत किया गया। मई 2026 में ही नीदरलैंड के साथ भी संबंधों को 'Special Strategic Partnership' तक ले जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। यानी पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब ने जहां एक त्रिकोण बनाया है, वहीं भारत ने इजराइल, फ्रांस, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, नीदरलैंड और खाड़ी के महत्वपूर्ण साझेदारों के साथ अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े रणनीतिक रिश्तों का ऐसा व्यापक नेटवर्क खड़ा किया है, जिसमें रक्षा तकनीक, मिसाइलें, समुद्री सुरक्षा,

कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा में संयुक्त शोध का अर्थ है कि भारत अपनी अगली पीढ़ी की सुरक्षा क्षमता केवल आज के युद्ध के लिए नहीं, बल्कि कल के युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखकर तैयार कर रहा है। साथ ही रक्षा उत्पादन में संयुक्त सहयोग, तकनीकी हस्तांतरण और घरेलू सह-उत्पादन की 'आत्मनिर्भर भारत' को सैन्य शक्ति से जोड़ते हैं। इसी संदर्भ में इजराइल की प्रस्तावित 'He&agon of Alliances' अवधारणा भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें भारत, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और अन्य साझेदारों के बीच सुरक्षा और आर्थिक सहयोग की परिकल्पना की गई है। इसका रणनीतिक संदेश यह है कि भारत पश्चिम एशिया और भूमध्यसागर में बन रहे नए शक्ति-संतुलन को केवल देख नहीं रहा, बल्कि अपने लिए वैकल्पिक रणनीतिक नेटवर्क भी तैयार कर रहा है। अब आते हैं मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सामूहिक प्रतिरोध का संकल्प लेते हुए कहा है कि तीनों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी पर हमला माना जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक, तीनों देशों के पास संयुक्त रूप से करीब 14 लाख सक्रिय सैन्यकर्मों, 3,415 विमान, 6,046 टैंक, 344 नौसैनिक परिसंपत्तियां और लगभग 124.4 अरब डॉलर का वार्षिक रक्षा बजट है। सऊदी अरब पूंजी और रणनीतिक भूगोल देता है, तुर्की रक्षा उद्योग, ड्रोन, मिसाइल और नौसैनिक तकनीक देता है, जबकि पाकिस्तान मानवबल, सैन्य अनुभव और परमाणु क्षमता लेकर आता है। लेकिन इस गठजोड़ को 'हस्तामिक नाटो' कह देना इसकी वास्तविक क्षमता का अंतिम

प्रमाण नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमला होने की स्थिति में बाकी सदस्य वास्तव में कितनी और किस प्रकार की सैन्य सहायता देने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल अभी कोई स्थायी केंद्रीय संयुक्त सैन्य कमान स्थापित नहीं हुई है। यानी राजनीतिक घोषणा और वास्तविक संयुक्त युद्ध क्षमता के बीच अभी लंबी दूरी है। साथ ही पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब के बीच बने नए रक्षा समीकरण को समझने के लिए केवल तीन देशों की सैन्य ताकत देखना काफी नहीं है। असली तस्वीर यह है कि पिछले एक साल में भारत ने भी अपनी रणनीतिक साझेदारियों और रक्षा सहयोग का दायरा तेजी से बढ़ाया है। अगस्त 2025 में भारत और फिलीपींस ने अपने संबंधों को औपचारिक रूप से Strategic Partnership यानि रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। फरवरी 2026 में भारत-इजराइल संबंधों को Special Strategic Partnership for Peace, Innovation and Prosperity तक पहुंचाया गया। फरवरी में ही भारत और फ्रांस ने अपने रिश्तों को Special Global Strategic Partnership के स्तर तक पहुंचाया। मई 2026 में भारत और वियतनाम ने संबंधों को Enhanced Comprehensive Strategic Partnership में बदल दिया। यूएई के साथ जनवरी 2026 में दोनों देशों ने Strategic Defence Partnership स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। इन साझेदारियों की खासियत यह है कि ये केवल कागज पर कूटनीतिक घोषणाएं नहीं हैं।

आज का राशि फल

मे़ष राशि: आज का दिन जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। वकीलों के लिये आज का दिन अच्छा रहेगा, नया केस हाथ लगेगा। आज खास लोगों के बीच किसी नई गतिविधि को लेकर पंथीर चर्चा होगी, जो कि सकारात्मक रहेगी। आज किसी मामले को लेकर विचारों में भावुकता रहेगी। आज कुछ लोग जलन की भावना से आपकी आलोचना कर सकते हैं।
वृष राशि: आज आपका दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। आज आपको किसी भी प्रकार के विवादों से दूर रहने की आवश्यकता है। आज व्यवसायिक काम समय पर बनते जाएंगे। विदेश संबंधी व्यवसाय में परिस्थितियां आपके अनुकूल होने के आसार हैं। आज ऑफिस में सहयोगियों की कार्यकुशलता से तारगेट समय पर पूरा हो जाएगा।
मिथुन राशि: आज आपके हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जायेगा। आज आप लेखन कार्यों में रुचि लेंगे आपका लेखन और अच्छा होगा। आज आपकी बातें दूसरों पर प्रभाव डलेगी। आज रोजमर्रा के कामों से हटकर कुछ नया सीखने में



समय बीतेगा। प्रॉपर्टी या वाहन की खरीददारी में लाभ की बेहतर स्थिति बनेगी। आध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों में आपका रुझान बढ़ेगा।
कर्क राशि: आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। किसी नयी बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा। थोड़ी सी बात पर परेशान होने के बजाय उसका हल ढूँढने की कोशिश करेंगे तो आपको सलुशन मिल जायेगा। आप जीवनसाथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है।
सिंह राशि: आज आपका दिन

अच्छा रहेगा। आज व्यवसाय में अतिरिक्त आय का साधन बनने वाला है। अगर आपका साझेदारी में बिजनेस करने का प्लान है तो ये डील आपके लिए फायदेमंद होगी। अधिकतर समय मार्केटिंग और बाहर की गतिविधियों में बीतेगा। इस राशि के सरकारी नौकरी कर रहे लोग अपने कार्यभार से संतुष्ट रहेंगे। आपको घर के बड़े से कुछ प्रेरणा मिलेगी। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे, वो सफल होगा।
कन्या राशि: आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज ध्यान रखे कि अगर प्रयासरत कार्यों में समस्या आती है तो इसकी वजह

आपकी एकाग्रता में कमी होगी। आज सम्मानित और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने से आपको कई नए विषयों की जानकारी मिलेगी। आज घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की खरीदारी संभव है। लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे।
तुला राशि: आज का दिन आपके लिये अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। आज घरवालों के साथ अच्छा समय बिताते को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। आज किसी समस्या को हल करने में आपका सहयोग सकारात्मक रहेगा। आस-पड़ोस की सामाजिक गतिविधियों में आपका वचस्व रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम हल होगा। आज नकारात्मक लोगों से दूर रहेंगे और आलस की स्थिति से बचेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जायेगा।
वृश्चिक राशि: आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज कार्यों को सुचारु रूप से करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। हालांकि सही समय पर उचित निर्णय लेने से जरूरत है। आज आप लेनेदेने को

जाएंगी। इस समय नया कार्य शुरू करें, आज के कामों को ही व्यवस्थित करने पर ध्यान देंगे। ऑफिस में आपका प्रभुत्व बना रहेगा। नवविवाहित दंपति के बीच आज मीठी नोक-झोंक होगी, इससे रिश्तों में और मिठास आयेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है।
धनु राशि: आज पूरे दिन भाग्य आपके साथ रहेगा। आज जल्दबाजी में फैसला न लें, न ही दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करें। आज किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाने की योजना बनायेंगे। साथ ही आय बढ़ाने के लिए नया प्लान बनायेंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मन बनायेंगे। कला जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है।
मकर राशि: आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। छात्रों को आज बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आज आप लेनेदेने को

स्थगित रखेंगे तो आने वाली किसी समस्या से बच जायेंगे। इस राशि के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपकी ऑफिशियल यात्रा संभव है।
कुंभ राशि: आज का दिन मिली-जुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज आपका दिन खुशनुमा बीतेगा। घर पर ही परिवारवालों के साथ धार्मिक कार्यों का आयोजन करेंगे। आज आपकी तरक्की के कई रास्ते खुलेंगे। ऑफिस के काम को थोड़ा संभलकर करने की जरूरत है, आपके काम की शिकायत कर सकता है। आज किसी से भी उलझने से आपको बचना चाहिए।
मीन राशि: आज आपको किसी अपने से अच्छी खबर मिलने के योग बने हुये है। आज व्यक्तिगत काम के समय आप घबराए की बजाय परिस्थितियों का समाधान ढूँढने का प्रयास करेंगे और इसमें आप सफल थी होगी। परिवारिक सदस्य की किसी उपलब्धि से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। मार्केटिंग की जाँच कर रहे लोगों से आज अच्छा क्लाइंट जुड़ेगा।

विकसित भारत, स्वर्ण आंध्रदू 2047 हर व्यक्ति का लक्ष्य बने: कलेक्टर



ऑंगोल, पेन पावर, 13 अगस्त: जिला कलेक्टर पी. राजा बाबू ने लोगों से व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित कर विकसित भारत और स्वर्ण

आंध्रदू2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। गुरुवार को प्रकाशम भवन से मिनी स्टेडियम तक भव्य तिरंगा

रैली आयोजित की गई। इसमें करीब 3,000 विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिक हाथों में राष्ट्रीय

ध्वज लेकर शामिल हुए। रैली देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ी। मिनी स्टेडियम में आयोजित समापन कार्यक्रम में कलेक्टर राजा बाबू ने कहा कि आज का स्वतंत्र भारत महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का परिणाम है। उन्होंने युवाओं से देश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए पांच दिनों तक 'हर घर तिरंगा', सैल्फी अभियान, पौधारोपण और तिरंगा रैलियां जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर रैली में शामिल लोगों ने विकसित भारत और स्वर्ण आंध्रदू2047 के लक्ष्यों में योगदान देने की शपथ ली। संयुक्त कलेक्टर कल्पना कुमार सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने रैली में भाग लिया।

मतदाता सूची संशोधन पारदर्शी तरीके से पूरा करें



राजमहेंद्रवरम, पेन पावर, 13 अगस्त: पूर्वी गोदावरी जिले की मतदाता सूची पर्यवेक्षक के. माधवी लता ने अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से समन्वय के साथ कार्य करते हुए पारदर्शी एवं

विश्वसनीय अंतिम मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों के

प्रतिनिधियों को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे तथा नोटिस, दावे और सुनवाई से संबंधित दस्तावेजों का उचित

रिकॉर्ड रखा जाए। जिला कलेक्टर कीर्ति चेकुरी ने बताया कि ईआरओ द्वारा निपटाए गए नोटिस और दावों की गुणवत्ता जांच के लिए कलेक्ट्रेट में विशेष व्यवस्था की गई है। एएसडी मतदाता सूचियां मतदान केंद्रों और संबंधित तहसीलदार कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई हैं तथा जिला वेबसाइट और भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई हैं। आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। नोटिस और दावों के निपटारे की प्रक्रिया 28 सितंबर 2026 तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

विजयवाड़ा में भव्य 'हर घर तिरंगा' रैली



विजयवाड़ा, पेन पावर, 13 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को विजयवाड़ा में भव्य 'हर घर

तिरंगा' रैली आयोजित की गई। जिला प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित रैली कलेक्ट्रेट से शुरू होकर इंदिरा गांधी स्टेडियम तक पहुंची। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, युवाओं, खिलाड़ियों,

अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भाग लिया। इस दौरान "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम्" के नारों से शहर गूंज उठा। जिला कलेक्टर

डॉ. जी. लक्ष्मीश ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हुए देश निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने 2047 तक गांवों, शहरों, राज्य और देश के विकास के लिए अभी से लक्ष्य निर्धारित कर सामूहिक प्रयास करने की अपील की। पुलिस आयुक्त एस.वी. राजशेखर बाबू ने कहा कि तिरंगा रैली से देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना और मजबूत होगी। उन्होंने स्वर्ण आंध्रदू2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। विजयवाड़ा नगर निगम आयुक्त एच.एम. ध्यान चंद्र ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' की भावना को प्रत्येक घर और परिवार तक पहुंचाने में लोगों की भागीदारी सराहनीय है।

अंगदान जीवनदान है: कलेक्टर राजाबाबू

ऑंगोल, पेन पावर, 13 अगस्त: जिला कलेक्टर पी. राजा बाबू ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने और इस महान कार्य में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंगदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर किम्स हॉस्पिटल्स, ऑंगोल की ओर से अंगदान के महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए 3 किलोमीटर की जागरूकता वॉक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर पी. राजा बाबू और जिला पुलिस अधीक्षक वी. हर्षवर्धन राजू ने कार्यक्रम में भाग लिया। ऑंगोल डीएसपी रायपाटी श्रीनिवास राव ने वॉक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएसपी श्रीनिवास राव ने कहा कि एक व्यक्ति के अंगदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने अंगदान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता बताई। वॉक कलेक्टर कार्यालय से शुरू होकर एसपी कार्यालय तक चली। डॉक्टरों, चिकित्सा एवं नर्सिंग कर्मचारियों, मेडिकल



छात्रों, स्वयंसेवकों और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर प्लेकार्ड और नारों के माध्यम से अंगदान का संदेश दिया। कार्यक्रम में किम्स हॉस्पिटल के सीओओ के. अंकित रेड्डी, डॉ. टी. श्रीहरि रेड्डी, चिकित्सक एवं अन्य विशेषज्ञ शामिल हुए।

कोंडारेड्डी जनजातीय युवाओं के लिए 45 दिवसीय निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण

रम्पाचोडवरम, 13 अगस्त: आईटीडीए परियोजना अधिकाारी एवं संयुक्त कलेक्टर एस. प्रशांत कुमार ने बताया कि कोंडारेड्डी (एसटी) जनजातीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ड्राई

वॉल फॉल्स सीलिंग (डीडब्ल्यूएफसी) क्षेत्र में 45 दिवसीय निःशुल्क आवासीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण 17 अगस्त से विजयवाड़ा में शुरू होगा। 18 से 35 वर्ष की आयु के

कोंडारेड्डी (एसटी) पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। कुल 20 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को निःशुल्क प्रशिक्षण, आवास एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाएं: कलेक्टर

विजयवाड़ा, पेन पावर, 13 अगस्त: विजयवाड़ा जिला कलेक्टर डॉ. जी. लक्ष्मीश ने अधिकारियों को मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और आवेदनों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में मतदान केंद्रों, मतदाता पंजीकरण तथा फॉर्म-6, 7 और 8 की समीक्षा की गई। 18 से 20 वर्ष के युवाओं के पंजीकरण के लिए कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में विशेष शिविर आयोजित करने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान ईआरओधईआरओ स्तर पर ही करने को कहा गया, ताकि उन्हें दूरस्थ कार्यालयों में न जाना पड़े। कलेक्टर लक्ष्मीश ने बताया कि 57 प्रतिशत



नोटिसों की डिलीवरी पूरी हो चुकी है। निर्धारित अवधि से लंबित लगभग 9,000 फॉर्म-6 और 6,000 फॉर्म-8 आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए 22, 23, 29 और 30 अगस्त को विशेष अभियान आयोजित किए जाएंगे।

मतदाता सूची का संशोधन पारदर्शी तरीके से पूरा करें



काकीनाडा, पेन पावर, 13 अगस्त: जिला कलेक्टर एम. एन. हरेश्वर प्रसाद ने अधिकारियों को विशेष गहन मतदाता सूची संशोधनदू2026 प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव की अध्यक्षता

में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में नोटिस जारी करने, बीएलओ बैठकों, मसौदा मतदाता सूची तथा फॉर्म-6, 7 और 8 की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बताया कि जिले के सभी 1,822 मतदान केंद्रों के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कुल 31,695 नोटिसों में से 7,335 वितरित किए गए हैं,

जबकि शेष 24,360 नोटिसों के वितरण की प्रक्रिया तेज की जा रही है। नए मतदाता पंजीकरण के लिए 7,724 फॉर्म-6, नाम हटाने से संबंधित 219 फॉर्म-7 और विवरण संशोधन के लिए 5,174 फॉर्म-8 आवेदन लंबित हैं। इनका सत्यापन कर शीघ्र निपटारा किया जाएगा। मतदाता जागरूकता के लिए 22, 23,

29 और 30 अगस्त को बृथ स्तर पर विशेष अभियान आयोजित किए जाएंगे। दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं और उनका निपटारा 28 सितंबर तक किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां युवाओं के लिए प्रेरणादायक

गंडेपल्ली, पेन पावर, 13 अगस्त: भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान उपलब्धियों को याद करते हुए युवाओं में वैज्ञानिक सोच, तकनीकी कौशल और नवाचार की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से आदित्य विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवसदू2026 भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ईनै) विभाग ने एम्स सिग्नल प्रोसेसिंग सोसाइटी स्टूडेंट ब्रांच चौपटर और एम्स विशाखापट्टनम बे सेक्शन कॉमसैक जॉइंट चौपटर के सहयोग से किया। आदित्य विश्वविद्यालय सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के करीब 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डॉ. टी. सुधीर कुमार ने अंतरिक्ष तकनीक में



सिग्नल प्रोसेसिंग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उपग्रह संचार, रडार, सैटेलाइट इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग और टेलीमेड्री के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कम्प्यूटर विज्ञान जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी सिग्नल प्रोसेसिंग महत्वपूर्ण भूमिका

निभाता है। विद्यार्थियों के लिए एआई आधारित पोस्टर एवं मॉडल प्रस्तुति तथा अंतरिक्ष तकनीक पर वि्वज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विजेताओं को पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के

डिप्टी प्रो-चांसलर डॉ. एम. श्रीनिवास रेड्डी, रजिस्ट्रार डॉ. जी. सुरेश, ईसीई विभागाध्यक्ष डॉ. सी. एच. जानकीदेवी, एम्स स्टूडेंट ब्रांच काउंसलर डॉ. वी. श्रीनिवास राव और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की डीन डॉ. जी. श्रीदेवी सहित अन्य उपस्थित रहे।

मतदाता सूची पर्यवेक्षक ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया

रम्पाचोडवरम, पेन पावर, 13 अगस्त: मतदाता सूची पर्यवेक्षक वी. प्रसन्न वेंकटेश ने गुरुवार को रम्पाचोडवरम विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने मारेडुमिल्ली गांव के मतदान केंद्र संख्या 179 और कुट्टावाड़ा गांव के मतदान केंद्र संख्या 172 का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाताओं की संख्या, जागरूकता कार्यक्रमों और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बीएलओ को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का



मतदाता के रूप में पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा मतदाता सूची में संशोधन और नाम हटाने की प्रक्रिया

सावधानीपूर्वक करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने पेद्दगुड्डा गांव स्थित एकलव्य मॉडल

आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। छात्र संख्या, शिक्षकों, पढ़ाई, भोजन की गुणवत्ता, कक्षाओं, रसोईघर, भंडारण कक्ष और स्वच्छता की समीक्षा की। उन्होंने नि्धारित मेन्यू के अनुसार विद्यार्थियों को प्रतिदिन ताजा और गर्म भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर सुरपति प्रशांत कुमार, आरडीओ के. स्वाति, तहसीलदार अम्माजी, उप तहसीलदार दोरकय्या और प्रधानाचार्य शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।



उम्र सिर्फ एक नंबर है, आत्मविश्वास व अंदाज कभी पुराने नहीं होते : ईशा कोप्पिकर



बढ़ती उम्र को लेकर अब लोगों की सोच भी बदल रही है। खासकर मनोरंजन जगत की अभिनेत्रियां अपने अनुभवों के साथ यह बताती नजर आती हैं कि उम्र किसी की खूबसूरती, आत्मविश्वास या पहचान तय नहीं करती। अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर भी इसी सोच को लेकर अपनी बात सामने रखती रही हैं। इस कड़ी में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उम्र, आत्मविश्वास, फिटनेस, मातृत्व, प्यार और जिंदगी में आए बदलावों को लेकर खुलकर बात की। ईशा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ खूबसूरत और स्टाइलिश तस्वीरें पोस्ट कीं और कहा, "उम्र सिर्फ एक नंबर है। अब मैं पहले से थोड़ी ज्यादा आत्मविश्वासी, अपनी पसंद को लेकर ज्यादा सजग और खुद को लेकर पहले से ज्यादा बेबाक हूं। असली खूबसूरती और अंदाज उम्र में नहीं, बल्कि इस बात में है कि ईसान समय के साथ खुद को कितना बेहतर बनाता है।" ईशा ने लिखा, "मैं अब बेहतर चुनाव करती हूं, गहराई से प्यार करती हूं और जिंदगी के हर पड़ाव को खास बनाने की कोशिश करती हूं। मैं वही लड़की हूं, लेकिन अब मेरे स्टैंडर्ड बेहतर हैं, सपने बड़े हैं, आसपास लोगों की संख्या कम है और यादें पहले से ज्यादा हैं।" ईशा की

बेटे करण संग सनी देओल ने जाना बंटवारे का सच कहा-नई पीढ़ी को समझना चाहिए



अभिनेता सनी देओल इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन में व्यस्त चल रहे हैं। बुधवार को उन्होंने बताया कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान वे अमृतसर पार्टिशन म्यूजियम गए थे। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे अपने बेटे करण के साथ नजर आ रहे हैं। अभिनेता ने इस वीडियो के जरिए बताया कि अमृतसर के म्यूजियम में बंटवारे के समय की बहुत सारी कहानी देखने को मिली। अभिनेता ने लिखा, फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के दौरान अमृतसर पार्टिशन म्यूजियम जाने का मौका मिला। वहां जाकर बंटवारे की ऐसी कई कहानियां जानने को मिलीं, जिनमें दर्द, हिंमत, बिछड़ने और फिर से जीवन शुरू करने की बातें हैं। इन कहानियों को सुनकर एहसास होता है कि

1947 के बंटवारे ने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। इतिहास के कुछ पन्ने दर्द से भरे हैं लेकिन उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है ताकि आने वाली

फिल्म 'बंटवारा 1947' भी भारत-पाकिस्तान विभाजन पर आधारित कहानी को बयां करती हैं। इसके जरिए निर्देशक राजकुमार संतोषी ने विभाजन के समय की कहानी

कैसेट किंग गुलशन कुमार की मौत के 29 साल बाद भी कायम है ये विरासत



गुलशन कुमार ने अपने जीवन में संगीत जगत को नई ऊंचाई दी थी लेकिन उनकी मौत के 29 साल बाद उनकी सबसे बड़ी कमाई शायद किसी दुकान, कैसेट या फिल्म से नहीं बल्कि एक ऐसे माध्यम से हो रही है जिसकी उन्होंने अपने समय में कल्पना भी नहीं की होगी। उन्हें 'कैसेट किंग' कहा जाता था और उन्होंने भक्ति संगीत को 1980 और 1990 के दशक में सस्ते कैसेटों के जरिए घर-घर पहुंचाया और आज वही संगीत मोबाइल फोन और इंटरनेट पर अरबों बार देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'श्री हनुमान चालीसा' का वह वीडियो है, जिसमें गुलशन कुमार दिखाई देते हैं। मई 2011 में टी-सीरीज के भक्ति चैनल पर आया यह वीडियो नवंबर 2025 में 5 अरब व्यूज पार कर गया। यानी गुलशन कुमार के जाने के करीब 14 साल बाद उनका चेहरा एक ऐसे डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा बना, जो दुनियाभर में चर्चा का विषय बना।

यहां कहानी सिर्फ 5 अरब व्यूज की नहीं है। दरअसल, यह वही बाजार है, जिसे गुलशन कुमार ने

अपने समय में पहचाना था। जब भारत में संगीत सुनने के लिए कैसेट खरीदे जाते थे, तब उन्होंने समझ लिया था कि भक्ति संगीत का बाजार बहुत बड़ा है। टी-सीरीज ने शुरुआती सालों में भजन और धार्मिक गीतों के कैसेट बड़े पैमाने पर निकाले। गुलशन कुमार की कारोबारी समझ यह थी कि संगीत केवल फिल्म देखने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। मंदिर जाने वाला, घर में पूजा करने वाला और छोटे शहर में रहने वाला व्यक्ति भी संगीत का बड़ा ग्राहक हो सकता है। बाद में यही सोच टी-सीरीज के डिवोशनल कैटलॉग की बड़ी ताकत बनी।

नयनतारा ने की 'टॉक्सिक' की निर्देशक गीतू मोहनदास की जमकर तारीफ बोलीं- 'वह हर कलाकार को अपना बना लेती हैं'



मैं उनके साथ मौजूद रही। यही चीज गीतू को एक अलग तरह की निर्देशक बनाती है। वह अपने कलाकारों को केवल फिल्म का हिस्सा नहीं मानतीं, बल्कि उनके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी बनाती हैं।

इस दौरान नयनतारा ने फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक भावुक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया, "एक बार शूटिंग के दौरान गीतू एक कलाकार को लेकर काफी भावुक हो गई थीं। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाईं। इसके बाद वह उस कलाकार के साथ कुछ देर तक रही, ताकि उसे अकेला न महसूस हो।"

उन्होंने आगे बताया कि जब गीतू से वापस आईं, तो हमने

साउथ सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रीन-अप्स' को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है। फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार यश मुख्य भूमिका में हैं, जबकि नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। फिल्म को लेकर चर्चा सिर्फ इसकी स्टारकास्ट और कहानी की वजह से नहीं है, बल्कि निर्देशक गीतू मोहनदास के काम करने के तरीके ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। अब फिल्म की अभिनेत्री नयनतारा ने गीतू की तारीफ की है। हाल ही में 'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में नयनतारा ने गीतू मोहनदास के साथ काम करने के

अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा, अब तक सभी लोग गीतू की एक निर्देशक के तौर पर खूब तारीफ कर चुके हैं, लेकिन मैं उनके व्यक्तित्व के उस पहलू के बारे में बात करना चाहती हूं, जो शायद पदों के पीछे नजर आता है। गीतू सिर्फ कलाकारों से उनका काम नहीं करवातीं, बल्कि उनकी भावनाओं को समझती हैं और मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी भी रहती हैं।

अभिनेत्री ने आगे कहा फिल्म की शूटिंग के दौरान कलाकारों को कई तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। किसी के लिए दिन अच्छा रहा तो किसी को मुश्किल सीन का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में गीतू ने निर्देशक होने के साथ-साथ एक मजबूत सहारे की भूमिका भी निभाई। वह हर स्थिति

सारा अली खान ने पंखे पर फेंक दी फेविकोल की बोतल, सस्पेंड होने की आ गई थी नौबत



बॉलीवुड में आने के बाद सारा अली खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ मजाकिया अंदाज के लिए भी पहचानी जाती हैं। वह अक्सर इंटरव्यू में जिंदगी की

दिया। उन्होंने बताया था कि एक बार स्कूल में उन्होंने पंखे पर फेविकोल फेंक दी थी और बात इतनी बढ़ गई कि स्कूल से सस्पेंड किए जाने की नौबत आ गई थी। सारा अली खान का जन्म 12 अगस्त 1995 को मुंबई में हुआ। वह अभिनेता सैफ अली खान और र

अभिनेत्री अमृता सिंह की बेटी हैं। उन का परिवार

किस्से का भी खुलासा किया। सारा ने बताया कि उन्हें जियोग्राफी की क्लास में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसी दौरान उन्होंने गोंद की एक बोतल पंखे की तरफ फेंक दी। बोतल टूट गई और फेविकोल पंखे और उसके आसपास फैल गया। मामला इतना आगे बढ़ा कि सस्पेंड होने की नौबत आ गई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद सारा ने अभिनय को करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने खुद बताया था कि कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान ही उन्हें लगा कि वह अभिनेत्री बनना चाहती हैं। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपने फिटनेस पर भी काफी काम किया। इसके बाद 2018 में उन्हें अभिषेक कपूर की फिल्म 'केदारनाथ' से बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला। फिल्म में उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत थे। सारा ने मुक्कु का किरदार निभाया और पहली ही फिल्म से दर्शकों का ध्यान खींचा।

उसी साल सारा की दूसरी फिल्म 'सिंबा' रिलीज हुई। रोहित शेट्टी की इस फिल्म में उनके साथ रणवीर सिंह थे। 'केदारनाथ' में गंभीर भूमिका के बाद 'सिंबा' में उनका चुलबुला अंदाज देखने को मिला। दोनों फिल्मों के एक ही साल में आने से सारा को शुरुआत में ही अलग-अलग तरह के किरदार करने का मौका मिला। 'केदारनाथ' के लिए उन्हें फिल्मफेयर, आइफा और स्क्रीन अवॉर्ड मिला।

इसके बाद सारा ने 'लव आज कल', 'कुली नंबर 1', 'अतरंगी रे', 'गैसलाइट', 'जरा हटके जरा बचके', 'मर्डर मुबारक', 'ऐ वतन मेरे वतन', 'रांकी और रानी की प्रेम कहानी' और 'स्काई फोर्स' जैसी फिल्मों में काम किया। 2025 में वह 'मेट्रो... इन दिनों' में भी नजर आईं। उनके करियर में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन सारा लगातार फिल्मों में काम कर रही हैं।